"भारत का इतिहास" पर पुस्तक लिखने के लिए समिति

5094. **श्री अजीत जोगी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु "समकालीन भारत का इतिहास" पुस्तक लिखने के लिए गठित इतिहासकारों की समिति ने इस पुस्तक का प्रारूप तैयार कर लिया है;

(ख) क्या उक्त प्रारूप को उसकी क्षेत्रीय सलाहकार समितियों को प्रचालित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के समकालीन इतिहास को लिखने के कार्य में सहायता देने हेतु गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की अवधि अगस्त, 1997 तक है ।

गुजरात में प्राथमिक शिक्षा

5095. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में और विशेषकर गुजरात में प्राथमिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने के लिये कोई कार्यक्रम आरम्भ किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ में राज्यवार कितने जिलों को शामिल किया जाता है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) (ख) से (ग) गुजरात में 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' नामक एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । यह कार्यक्रम, जिला विशेष आयोजना एवं एकल लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए कार्य-नीति को कार्यान्वित करता है । योजनाओं की आंशिक कार्यान्वयन की अपेक्षा चुने हुए जिलों में प्राथमिक शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से पुर्नगठित करना, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है । इस कार्यक्रम में उन जिलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय औसत दर से कम है तथा जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियानों ने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सफलतापूर्वक मांग पैदा की है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रारम्भ में 7 राज्यों के 42 जिलों को चुना गया है । इन जिलों में असम के 4 जिले, हरियाणा के 4, कर्नाटक के 4, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 5 तमिलनाडु के 3 तथा केरल के तीन जिले शामिल हैं ।

उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान

5096. **श्री ईश्वर यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी महाविद्यालय/विद्यालय को अनुदान दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड/प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं;

(ख) पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में किन-किन महाविद्यालयों को अनुदान दिया गया और किस उद्देश्य हेतु दिया गया; और

(ग) क्या सरकार को इन अनुदानों के आवंटन में भेदभाव किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री